विशेष रूप से बस्तर जिले में नक्सलवादियों की बढ़ी हुई गतिविधियों के बारे में जानकारी है, जिस के बारे में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार चिन्तित है। 3 अगस्त, 1991 को गृह मंत्री ने एक बैठक की जिसमें मध्य प्रदेश सहित प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक में हुए विचार-विमर्श के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति हुई कि राज्य सरकारें कार्रवाई योजना तैयार करेंगी जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने और समस्या से निपटने के लिए आवश्यक विकास उपाय भी निहित होंगे। चूंकि आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा के नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र एक दूसरे से सटे हुए हैं, अतः यह महसूस किया गया कि इन चार राज्यों के नक्सलवाद विरोधी उपायों को समन्वित किया जाए। इस दिशा में चार राज्यों की सरकारी स्तर की अनुवर्ती बैठकें की गई और पुलिस कार्रवाई और विश्वास और प्रशासनिक उपायों का समन्वित करने का निर्णय लिया गया।

Loss of revenue due to reduction in excise duty on beer in Delhi

264. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether reduction in excise duty on chilled beer in Delhi is likely to result in loss of revenue to the Delhi Administration; if so, what would be the amount of such loss alongwith the year-wise amount of revenue earned on account of sale of beer and other liquors during the years 1990-91 and 1991-92 respectively?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): The Delhi Administration has reported that there is no proposal under its consideration for reduction in excise duty on chilled beer in Delhi. The revenue generated from the sale of beer and other liquors during 1990-91 and 1991-92 was Rs. 136.10 crores and Rs. 163.53 crores respectively.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में हिन्दी का प्रयोग

265. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1988 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ये निदेश जारी किए गए थे कि सरकारी क्षेत्र के सभी बड़े उपक्रम अपना विधि से संबंधित समस्त कार्य हिन्दी में करने की व्यवस्था स्वयं करेंगे; यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) समस्त कार्य हिन्दी में करने के लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के प्रथम खण्ड पर दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 को जारी राष्ट्रपति के निदेशों में उपक्रमों के विधिक साहित्य के अनुवाद के संबंध में ही चर्चा की गई थी, तथा यह कहा गया था कि विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड केवल सरकारी विभागों और कार्यालयों के विधिक अनुवाद कार्य के लिए है। बैंकों, बीमा कम्पनियों और बड़े उपक्रमों को अपने विधिक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड उनके मार्गदर्शन के लिए कुछ मानक प्रारूप तैयार कर देगा और विधि अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। विधि एवं न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग बड़े उपक्रमों के मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत है।

कर्णाटक में दंगे

266. **मौलाना औबेदुल्ला खान आजमी :**

चौधरी हरि सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेलगाम, कर्णाटक में हाल ही में हुए सांप्रदायिक दंगों से जान और माल का कितना नुकसान हुआ;

(ख) इन दंगों के क्या कारण थे;

(ग) दंगा पीड़ित व्यक्तियों को क्या सहायता प्रदान की गई है;

(घ) दंगों को रोकने में असफलता के दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) ऐसे दंगों को रोकने के लिए राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिये गये हैं; और

(च) त्वरित कार्य बल के गठन की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस संबंध में यदि कोई विलम्ब हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (घ) लोक व्यवस्था को बनाए रखना संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II राज्य सूची में शामिल है और अतः यह राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। कर्नाटक राज्य सरकार से एक रिपोर्ट की मांग की गई है।

(ङ) केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक हिंसा की रोक-थाम करने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा उनको राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित किया है।

(च) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 बटालियनों को परिवर्तित करके रेपिड एक्शन फोर्स का गठन किया जा चुका है।

बंगलादेश से अवैध प्रवेश रोकने के लिए उपाय

267. **श्री राम जेठमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सुरक्षा बल ने बंगलादेश से हमारे देश में लोगों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए सरकार को हाल ही में कतिपय उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों को मान लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की क्या योजनाएं हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) अवैध प्रवेश को रोकने के लिए विभिन्न उपाय करने पर समय-समय पर सभी संबंधित अभिकरणों के साथ परामर्श करके विचार किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

Kashmir Problem

268. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that, besides a political settlement of the Kashmir issue with militants, a number of administrative and other steps including delimitation of constituencies, both Parliamentary and Assembly, are required to be taken before general elections can be held in Jammu and Kashmir for restoration of a democratic Government in the State; and

(b) if so, the details thereof and the action taken so far in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) The number of Assembly seats have been increased by 11 by an amendment to the J&K Constitution in 1988 and the elections can take place only after the Delimitation work is completed by the Delimitation Commission, reconstituted in 1991.